12.00 Noon

the Government of India to give due importance to Kolkata, the Gateway of Eastern India, and also plan aviation destinations for Buddhist religious tourism centres which are situated at nearby towns. Thank you.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I associate myself with the Zero Hour submission of Shri Ahamed Hassan. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission of Shri Ahamed Hassan. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI WANSUK SYIEM (Meghalaya): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission of Shri Ahamed Hassan. ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission of Shri Ahamed Hassan. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why do you disturb? ...(*Interruptions*)... What should I do? ...(*Interruptions*)...Should I go and change it? ...(*Interruptions*)... Smt. Chhaya Verma. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती छाया वर्माः उपसभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के महासमुन्द जिले के जलकी गांव के विष्णु साहू नाम के एक किसान ने अपनी चार एकड़ फॉरेस्ट जमीन नहर बनाने के लिए शासन को दी थी। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Time is over. Mrs. Verma, you repeat your notice; and others also, who have not got the opportunity, may repeat their notices for the next day.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Question hour. Question No. 211.

Sanctioned work charged posts in Railways

*211. DR. ANIL KUMAR SAHANI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether work charged posts of officers in Railways are being utilized as revenue posts in zonal railways, especially in the newly created zones;

(b) whether all these work charged posts are currently sanctioned or officers are working on these posts beyond the sanctioned period, if so, the details of number of

posts for which sanction has lapsed and the officers are still working thereon; and

(c) the steps being taken by the Ministry to convert the work charged posts, which are in existence for more than three years, to revenue posts?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI SURESH PRABHU): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Revenue posts and Work charged posts co-exist on the Railways and Gazetted officers are posted against these in old as well as newly created Zonal Railways. Revenue posts are posts carrying a definite rate of pay sanctioned without limit of time. Work charged posts are created on 'worth of charge' basis against sanctioned works/ detailed estimates and outlay, for a 'basket of projects' depending on total allotment of funds and yardsticks stipulated by the Efficiency and Research Directorate for the corresponding financial year. The Work charged posts facilitate planning, execution and supervision of various Projects. The existing operation/ maintenance of Railways and project planning, execution and supervision, both in old and newly created zones are managed by officers working against Revenue and Work charged posts respectively.

(b) Work charged Posts are normally created initially for a period of one year and are extended on a year to year basis depending on requirement and allotment of funds. Extension of Work charged posts is done by Competent Authority after due process and scrutiny at various levels. Presently, total number of Work charged gazetted posts in various grades on Indian Railways is 6434. Out of 6434 Work charged posts, currency of 6275 posts have been duly extended. There are only 159 posts for which the process for extension of currency is underway. For payment of salary to the incumbents of these 159 posts, General Managers are authorised to issue Provisional Payment Authority (PPA) to Junior Administrative Grade (JAG) and below posts. For Senior Administrative Grade (SAG) and Higher Administrative Grade (HAG) posts, Provisional Payment Authority is being issued by Railway Board.

(c) There is no provision for conversion of Work charged posts into Revenue posts.

डा. अनिल कुमार साहनीः सभापति जी, वर्ष 2016 के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय रेल में 6,833 work charged अधिकारियों के पद थे, जो कुल अधिकारियों का 35 प्रतिशत है। इससे सिद्ध होता है कि work charged पदों का इस्तेमाल regular nature के कार्य में किया जा रहा है, जिसके कारण अन्य अधिकारियों की पदोन्नित बाधित हो रही है।

श्री सभापतिः आप सवाल पूछिए। ...(**व्यवधान**)...

डा. अनिल कुमार साहनीः मैं वहीं आ रहा हूं, सर। Work charged पदों में ग्रुप-ए का 5,400 रुपए के ग्रेड में, कोई भी पद नहीं है, जिसके कारण ग्रुप-बी के अधिकारियों की पदोन्नति में दिक्कत आ रही है। इन अधिकारियों को 15 से 20 साल तक पदोन्नित नहीं मिल पाती। मैं माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्रुप-बी के जिन अधिकारियों की पदोन्नति रुकी हुई है, उन्हें next grade में पदोन्नति देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री सुरेश प्रभुः महोदय, माननीय सदस्य रेलवे के कार्यकरण के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, क्योंकि यदि मैं गलत नहीं हूं, तो शायद कुछ समय उन्होंने रेलवे में काम भी किया था, इसलिए उन्हें अच्छी जानकारी है कि रेलवे में कारोबार कैसे चलता है। रेलवे में दो तरह की posts हैं — एक revenue posts और दूसरी work charged posts. Work charged posts कुछ समय के लिए create की जाती हैं, ज्यादातर एक साल के लिए, जिन्हें कभी-कभी बढ़ाया भी जा सकता है। उसका कारण यह है कि जहां projects चल रहे हैं, उन projects को ठीक तरह से चलाने के लिए और लोगों पर निगरानी रखने के लिए ये posts create की जाती हैं, ताकि projects समय पर पूरे हों। मैंने इस प्रश्न के उत्तर में भी बताया है कि हमारे यहां जितनी भी posts हैं, वे सभी posts सिर्फ इसी कारण create की गई हैं कि जो रेलवे में जो काम चल रहे हैं, उन पर निगरानी रखी जा सके। आपको शायद यह जानकर खुशी भी होगी कि पहले रेलवे में 35-40 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा, विभिन्न projects की implementation के लिए, capital expenditure नहीं दिया जाता था, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी के कार्यकाल में, पिछले तीन सालों में हम लोगों ने capital expenditure को बढ़ाकर लगभग 3,75,000 करोड़ रुपए किया है। इस कारण बड़ी मात्रा में projects भी चल रहे हैं। जब projects चलेंगे तो उन पर निगरानी रखने की भी ज्यादा ज़रूरत होती है। रेलवे की Efficiency and Projects Organization जो निर्णय लेती है, उसके अनुसार projects लिए जाते हैं। आपको संदेह है कि क्या इस वजह से promotions नहीं हो रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। फिर भी, जब आपने कहा है, तो मैं फिर से इसे देख लेता हूं।

डा. अनिल कुमार साहनीः सभापति जी, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया, मैं उससे संतुष्ट हूं। साथ ही SAG के ऊपर के पदों पर, स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में अधिकारी तैनात हैं, जिन्हें प्रशिक्षण हेतु अवकाश पर भेजकर समायोजित किया जा रहा है, जिससे रेलवे के राजस्व को क्षति हो रही है। आप किसी भी ज़ोन से इसकी figures मंगाकर देख सकते हैं कि किस ज़ोन में कितनी क्षति हुई है। मुझे यह जानकारी भी प्राप्त हुई है कि जो नए ज़ोन बनाए गए हैं, उनमें ब्रांच अधिकारियों के पद भी work charged पर हैं, जो उचित नहीं है। मेरा प्रश्न है कि इस स्थिति पर ध्यान देकर, क्या ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे नए सृजित पदों को नियमित पदों में शामिल कर लिया जाए ताकि नए खुले ज़ोन्स में सुचारु रूप से कार्य हो सके?

श्री सुरेश प्रभुः महोदय, पिछले तीन सालों में इस तरह के किसी पद का निर्माण नहीं हुआ है। यह बिल्कुल सही है। मैंने शुरू में कहा कि work charged posts किस कारण create की जाती हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि work charged posts को revenue posts में convert नहीं किया जा सकता। It is like an ad hoc arrangement. इससे किसी की job को खतरा होगा, ऐसी स्थिति नहीं है। उनके pay scales भी वैसे ही होते हैं, जो revenue scales में होते हैं। मुझे लगता है कि आपको इसकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी, जैसा आपने कहा है, उस पर हम जरूर ध्यान देंगे।

SHRI P. BHATTACHARYA: Sir, I would like to know from the hon. Minister the number of new zones the Government is planning to open under the Railway Ministry. I am asking this because the problem which is being faced cannot be sorted out by opening new zones. What is the Government's plan about that?

SHRI SURESH PRABHU: Sir, it is completely a different kind of question. I would like to tell the hon. Member that we have noted his suggestion. This is pertaining to the work charged posts and what you are asking is a little different. But, of course, I have noted your concern. We will look into it.

श्री संजय राउतः सर, ये जो वर्क चार्ज पोस्ट्स हैं, ये कोई प्रॉपर पोस्ट्स नहीं हैं। उनमें जिन कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, उनकी काफी परेशानियां हैं। उनको छुट्टी नहीं मिलती है, सैंक्शन नहीं होती है और सुविधाएँ नहीं मिलती हैं। यह एक ऐडजस्टमेंट है। कमर्चारी के जो अधिकार होते हैं, वे भी उनको नहीं मिलते हैं। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, यह कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जब आप वहां इंजीनियिंरग, इलेक्ट्रीकल और कंस्ट्रक्शन जैसे डिपार्टमेंट्स से हज़ारों लोगों की ट्रांसफर करते हैं, तो वहां के जो मूल लोग हैं, उनकी क्षमता का भी नुकसान होता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों का सही इस्तेमाल कैसे हो सकता है और वर्क चार्ज पोस्ट्स की जो समस्याएँ हैं, उनका परमानेंट सॉल्यूशन आप क्या निकाल सकते हैं?

श्री सुरेश प्रभुः सर, सबसे पहले मैं उसके बारे में कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ। वर्क चार्ज पोस्ट्स ऐसी पोस्ट्स नहीं हैं कि उनमें बाहर से आदमी को लाकर अप्वाइंट किया जाए। हाल ही में काम करने वाले जो अधिकारी हैं, वे अधिकारी उन वर्क चार्ज पोस्ट्स पर ट्रांसफर किए जाते हैं और वहां टेम्परेरली पोस्ट किए जाते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति नहीं है। उनकी जो वर्क कंडिशंस हैं, उनकी जो सैलरी है, उनको मिलने वाले जो और बेनिफिट्स हैं, उनमें कोई भी कटौती नहीं होती और उसके लिए इस तरह की कोई संभावना नहीं है। जैसा मैंने कहा कि यह व्यवस्था काफी सालों से चल रही है और यह व्यवस्था शायद यह सोचकर बनाई गई थी कि यदि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हर ज़ोन में basket of projects को साथ में लेते हुए, उसके ऊपर अच्छी तरह से निगरानी रखने के लिए यदि इस तरह की एक व्यवस्था बनाई जाए, तो उसका लाभ हो सकता है। लेकिन, इस तरह की स्थिति नहीं है कि उनके वेतनमान या सर्विस कंडिशंस में किसी भी तरह की क्षति हो रही हो।

SHRI MANISH GUPTA: Sir, the issue of 'work charged' staff in Railways is an issue which is very old. It has been continuing for many years. You would have noticed that in other Departments of the Government also the 'work charged' staff is a serious issue. Mr. Chairman, Sir, through you, I would like to know from the hon. Minister whether the Railways is deploying any other policy to control this malaise. I would also like to know whether something like benchmarking of manpower productivity ratio is being continuously done. This is a useful tool because it controls the dynamism and the dynamics of the work charge staff. Thank you.

SHRI SURESH PRABHU: Sir, as I said, these are posts created to meet a particular contingency. Typically, the tenure of this post is one year. Sometimes, it gets extended depending upon the work. But, typically, it is something which is an arrangement made to meet a particular situation. Therefore, this is the contingency which is created. Sir, the hon. Member has asked a very valid point. Let me clarify that these are not temporary workers who are hired; this is not a work charged post. Work charged posts are the same officers posted from one position to another position. They are all gazetted officers. Currently, there are about 12,250 gazetted officers posted like this. They are all gazetted officers; they are not junior officers.

Number two, you asked me what could be a durable arrangement that can be worked out. Sir, if you recall, I had announced in my Railway Budget speech that we will create a project development and project implementation organization. The kind of projects that we are going to implement in Railways are under implementation considering the magnitude, considering the complexities, considering the speed at which they are getting implemented and also considering the requirement of future. If you take all that into consideration, then, we will need, probably, a different kind of organisation. Sir, I would like to inform the House that pursuant to that announcement that was made in my Budget Speech, we are already working out a project development organization. The work is already entrusted to a consultancy which is working on it, and I will inform the House as soon as it is completed. But the point is well taken that we need to think about a completely different organization.

Sir, another point – just to answer the question of the hon. Member -- is, only a few days ago, we had called all our chief construction officers from different zones and I asked them, if possible, we can create a project team, which will complete the project and till that time they will be there so that the responsibility of completion of project will lie particularly on some specific officers because we are seeing that the team gets dismantled, new officers come and they keep blaming each other. So, I asked them, can we take note of that? So, this is another arrangement that we are trying to think about immediately.

Also, Sir, – and last point – what we are thinking about is a reward, that is, an incentive scheme. If you complete the project before time, at less cost, something like an incentive can be worked out. If you delay the project and there is actually a cost or time over-run, then there can be some disincentive which can be worked out. So, this is also something which we are thinking about.